अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 17 जनवरी 2023

ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे, जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। - महात्मा गांधी

नए-नवेले पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक हुए हादसे ने एक बार फिर नेपाल की कमजोर विमानन व्यवस्था की ओर ध्यान खींचा है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि यह हवाई अड्डा चीन के कर्ज से तैयार हुआ है, जो इसे नेपाल के दावे के विपरीत बीआरआई का हिस्सा बता रहा है।

पोखरा विमान हादसे के सबक

नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में रविवार को हुए भीषण विमान हादसे के ब्योरे बता रहे हैं कि महज कुछ मिनट के भीतर कैसे सब कुछ खत्म हो गया। यति एयरलाइंस का यह विमान काठमांडू से रवाना हुआ था और पोखरा के नए-नवेले हवाई अड्डे पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही सेती नदी के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त होकर एक गहरी खाई में गिर गया। विमान में चालक दल सहित कुल 72 लोग सवार थे और इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई बचा भी होगा। मृतकों में शामिल पांच भारतीयों में से चार तो अकेले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निवासी थे। विमान हादसों में अमूमन किसी के बच निकलने के अवसर बहुत कम होते हैं और यह विमान तो कई टुकड़ों में बंट गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें सवार यात्रियों की क्या हालत हो गई होगी। इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और नेपाल सरकार ने जांच के लिए एक समिति भी बना दी है, फिर भी हादसे के कारणों के बारे में कुछ समय बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन हिमालय की गोद में बसे और पहाड़ियों से घिरे नेपाल का विमानन क्षेत्र में जो बदतर रिकॉर्ड है, उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। 1992 में काठमांडू के नजदीक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के भीषण विमान हादसे के तीन दशक बाद यह सबसे बड़ा विमान हादसा है। नेपाल की विमानन सेवा और हवाई अड्डों को सुरक्षित नहीं माना जाता और इसी वजह से 2013 में यूरोपीय संघ ने नेपाल में विमान हादसे की उच्च दर की वजह से नेपाली विमान सेवाओं पर रोक लगा दी थी, जो अब भी कायम है। निस्संदेह नेपाल की भौगोलिक स्थिति और मौसम के कारण उड़ानों में दिक्कतें आती हैं, लेकिन पोखरा हवाई अड्डे को लेकर चीन और नेपाल के बीच जो विवाद हुआ है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। दरअसल दो हफ्ते पहले जिस दिन नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने इसका उद्घाटन किया, उसी दिन चीनी दूतावास ने एकतरफा

घोषणा कर दी कि पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन-नेपाल बीआरआई (बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव) से तैयार हुआ है। यह हवाई अड्डा चीन से मिले कर्ज से बना जरूर है, लेकिन नेपाल का दावा है कि यह बीआरआई का हिस्सा नहीं है। जाहिर है, नेपाल के लिए यह बहुत नाजुक समय है, ऐसे में चीन की रणनीतिक चालाकियों पर नजर रखने की भी जरूरत है।

रंग लाया नारिकुरवार समुदाय का संघर्ष

अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने के संघर्ष में तमिलनाडु के नारिकुरवार समुदाय की जीत सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है-जो यह साबित करता है कि विभिन्न स्तरों पर संघर्ष से किसी समुदाय को सफलता मिल सकती है।

पिछले वर्ष दिसंबर के प्रारंभ में लोकसभा और राज्यसभा ने नारिकुरवार (प्रस्तावित बदले हुए नाम नारिकोरवन के साथ) और कुरुविक्करण समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए मतदान किया। दो जनवरी, 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने को नारिकुरवार समुदाय ने अपनी जीत बताते हुए कहा कि 'यह पहली बार है, जब हमारे अनुरोध को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है।'

नारिकुरवार अर्ध-खानाबदोश समुदाय है, जो मुख्यतः तमिलनाडु में रहता है। इस समुदाय के लोग मनके बनाने के अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वे मंदिरों के आगे और त्योहारों के दौरान बेचते हैं। हालांकि, जंगलों की जानकारी, हथियारों के इस्तेमाल और लंबी दूरी तक यात्रा करने की क्षमता के कारण वे ज्यादातर शिकारियों के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। अतीत पर गर्व करने वाले ये लोग अपने पूर्वजों के उत्तर भारत से दक्षिणी क्षेत्रों में जाने की कहानियां सुनाते हैं, जहां विभिन्न बदलावों के बावजूद उन्होंने अपनी घुमंतू जीवन शैली बनाए रखी है।

क्रिस्टीना-इओना ड्रैगोमिर

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं औपचारिक रोजगार तक नारिकुरवार समुदाय की पहुंच सीमित है। पिछले छह दशकों से ये लोग गरीबी से बाहर निकलने और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच बनाने का सपना देखते रहे हैं। अब जाकर उन्होंने अपनी पहचान के पहले कदम के रूप में कानूनी दर्जा हासिल किया है। आरक्षण की मौजूदा प्रणाली उनके अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक गतिशीलता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब तक नारिकुरवारों को सबसे पिछड़े वर्ग (एमबीसी) के रूप में मान्यता दी गई थी, पर इससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में उनकी पहुंच सीमित ही रही।

तैंतीस वर्षीय उच्च शिक्षित नारिकुरवार नेता राजशेखरन जानते हैं कि

शिक्षा से क्या लाभ होते हैं, और उन्हें यकीन है कि जब नारिकुरवारों की नई पीढ़ी औपचारिक शिक्षा पाएगी, तो वह अपने समुदाय की नियति को बदलने में सक्षम होगी। उनके मुताबिक, अभी वे संसाधनों एवं अन्य चीजों के लिए ज्यादा ताकतवर समुदायों के साथ आरक्षित सीटों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तमिलनाडु में अन्य एमबीसी समुदाय बेहतर संगठित हैं, अधिक सामाजिक-आर्थिक संसाधनों के साथ शिक्षित हैं, इसलिए वे अधिकारों तक पहुंच बना रहे हैं। इसलिए राजशेखरन नारिकुरवारों को एमबीसी से एसटी दर्जा दिए जाने के प्रबल समर्थक हैं। नारिकुरवार समुदाय विशिष्ट आदिवासी समूह नहीं है, जो स्पष्टतः एसटी कोटे के अंतर्गत आता है। एसटी दर्जे का दावा करने वाले अन्य समुदायों के विपरीत नारिकुरवार पैतृक जमीन का दावा नहीं करते, पर खानाबदोश के रूप में पहचाने जाते हैं और खुद को आपराधिक समुदायों से अलग करने की कोशिश करते हैं।

उन्हें अक्सर उन नेताओं का समर्थन नहीं मिलता, जो इस छोटे से समुदाय को महत्वपूर्ण वोट बैंक नहीं मानते। उन्हें एसटी समुदायों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जो सीमित संसाधनों और आरक्षित सीटों को एक और समुदाय के साथ साझा नहीं करना चाहते।

एसटी का दर्जा पाने से पहले इस समुदाय को कई राजनीतिक मोर्चों पर जूझना पड़ा। उनके संघर्ष ने तीन दशक पहले राजनीतिक आकार लेना शुरू किया, जब उन्होंने राज्य सरकार के सामने अर्जी लगाई और कई राजनेताओं ने उनके प्रति सहानुभूति जताई। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति किसी भी अन्य राज्य की राजनीति की तरह अस्थिर है। सरकार बदलने के बाद इस समुदाय ने अपना समर्थन खो दिया, पर वहा डिगा नहीं। इसने सत्ता में बैठी सरकार के पास अर्जी दी। कई पत्र लिखे, लेकिन वे अनुत्तरित रह गए।

जब इन लोगों ने देखा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उनके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे, तो उन्होंने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू किए। राज्य सरकार का पीछा करने के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2016 से वे दिल्ली की संगठित यात्राएं कर रहे थे और कठिन मौसमी स्थितियों के बावजूद जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। मीडिया की उपेक्षा के बावजूद वे अपनी मांग पर डटे रहे।

नारिकुरवारों को एसटी सूची में जोड़ने का विधेयक कई बार लोकसभा में पेश किया गया। वर्ष 2016 में यह उसी दिन लोकसभा के पटल पर चर्चा के लिए रखा गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक नोटबंदी की घोषणा की थी। नतीजतन देश भर में अफरातफरी के चलते उस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। उस झटके के बावजूद वापस तमिलनाडु लौटकर नारिकुरवारों ने अपने समुदाय के सामने तथ्यों को पेश किया और उन्हें एसटी का दर्जा पाने के महत्व के बारे में बताया।

इस बार उनके राजनीतिक प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। जनसंचार माध्यमों की मदद से नारिकुरवारों ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन की वकालत की और वैश्विक विद्वानों और संगठनों के साथ नियमित रूप से जुड़े रहे। इस क्रम में उन्होंने अपना एक अलग नाम रखा। कई सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप आज नारिकुरवार समुदाय अपने नए अधिग्रहीत एसटी दर्जे का भारी उम्मीद के साथ जश्न मना रहा है। अनुसूचित समुदाय की 53 वर्षीय सचिव अनुराधा कहती हैं, 'इस एसटी दर्जे के माध्यम से वर्षों के संघर्ष के बाद हम शिक्षा, रोजगार के अवसर, आजीविका और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तक पहुंच सकते हैं।'

नारिकुरवारों की जीत सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है-एक ऐसा कदम, जो यह साबित करता है कि विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर अथक और जटिल रणनीति बनाने से किसी समुदाय को सफलता मिल सकती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। भारत में आरक्षण प्रणाली की अक्सर आलोचना की जाती है, इसे खत्म करने या इसका विस्तार करने के लिए तर्क दिए जाते हैं। सात दशक से भी पहले बनाई गई इस व्यवस्था में आज भारत की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। इस क्रम में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वंचित समूहों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता के लिए एक मार्ग बनाना होगा।

-लेखिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में लिबरल स्टडीज में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

edit@amarujala.com

एन जी रंगा
(1900–1995)

आजादी के अमृत कथन

यह नितांत आवश्यक है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार गिरावट की इस समस्या पर पूरी सरकार गंभीरता से विचार करे।

कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण अतिआवश्यक

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री किशनचंद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन को इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले (कृषि वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण) पर चर्चा करने का अवसर दिया। श्रीमान, यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यदि कृषि उत्पादों की कीमतों को इतना कम करने की अनुमति दी जाती है कि किसानों के लिए कोई मार्जिन नहीं रह जाए और वे अपनी जरूरतें पूरी करने में अक्षम हो जाएं, तो हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से नष्ट हो जाएगी कि हमें आपदा का सामना करना पड़ेगा। वैसे में, बाकी लोग अपनी खुद की समृद्धि को बहुत लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं, यदि उनके सबसे अच्छे उपभोक्ता सेवाओं और सामान के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं?

यदि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो सरकार को बुनियादी स्तर पर ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जिनसे कृषि उत्पादों की कीमत स्थिर की जा सके और जिसे लाभकारी तथा उचित माना जा सके।

पिछली आर्थिक मंदी के दौरान अत्यधिक औद्योगिक देश अमेरिका के लोगों के लिए भी यह बात बहुत स्पष्ट हो गई, जब उन्होंने अपने कारखानों को बंद पाया, उनके बड़े शहरों में बेरोजगार लोगों की भीड़ लगी रही, उनके अपने तथाकथित समृद्ध और अत्यधिक भुगतान वाले श्रमिकों और पेशेवरों के साथ-साथ बुद्धिजीवियों को भीख मांगनी पड़ी और रोटी के लिए कतारों में शामिल होना पड़ा। तब वहां यह महसूस किया गया कि अगर औद्योगिक मशीनरी को रफ्तार देनी है और उनके पेशेवरों के साथ-साथ मजदूर वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना है, तो उन्हें तुरंत कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ानी होंगी। रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई सलाह के विपरीत उस समय के अमेरिकी नेतृत्व ने कृषि उपज की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि का रास्ता चुना। इसे एक कृत्रिम उपाय कहा गया और तुरंत किसानों की कर्ज लेने की क्षमता बढ़ गई; बैंक अपने ऋणों की वसूली के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने और किसानों को नए ऋण देने के लिए भी तैयार थे; किसान इस पैसे को कृषि में निवेश करने को तैयार थे। वहां अतिरिक्त उपज भंडारण की व्यवस्था थी, जिससे कृषि उत्पादन सही तरीके से किया जा सके। इस तरह एक बार फिर उद्योग और वाणिज्य के पहिए चलने लगे और वे अपनी आर्थिक मंदी से उबर पाए। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है।

शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए लोगों को यह एहसास हो गया है कि हमारी मौद्रिक नीति में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन, उन्होंने यह महसूस करने की जहमत नहीं उठाई कि शहरों में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या प्रत्यक्ष रूप से उस अदृश्य तरीके के कारण है, जिसमें बहुत लंबे समय से कृषकों का शोषण किया जाता रहा है; कृषि उत्पादों की कीमतों में निरंतर गिरावट से अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों के दौरान कमजोर हो गई है, जिसके चलते हमारे किसान उद्योगपतियों, पेशेवरों, बुद्धिजीवियों और शहरों के ऐसे अन्य लोगों की सेवाओं की मांग और उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, और हमारे लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं को एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करना है, तो बुनियादी स्तर पर सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे कृषि उत्पादों की कीमत स्थिर की जा सके और जिसे लाभकारी माना जा सके। इसलिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार गिरावट पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

-किसान नेता व सांसद एन जी रंगा के 26 नवंबर, 1954 को राज्यसभा में दिए भाषण के अंश।

दूसरा पहलू

स्विट्जरलैंड में बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और बर्फ गायब हो रही है, जिससे स्कीइंग उद्योग संकट में है।

बर्फ घटने से पहचान खो रहे स्विट्जरलैंड के गांव

स्विट्जरलैंड के बर्फीले इलाके के एक गेस्ट हाउस में घुसते हुए एक स्कीइंग रिजॉर्ट के निदेशक साइमन बिसिज ने जो दृश्य देखा, उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जनवरी के इस महीने में लकड़ी के इस भव्य गेस्ट हाउस को भरा हुआ होना चाहिए था, जिसमें बुजुर्ग लोग कुर्सियों पर बैठकर गर्म पेय का आनंद लेते हुए दूर बर्फ में अपने बच्चों को स्कीइंग करते हुए देख रहे होते। इसके बजाय गेस्ट हाउस खाली था और खिड़की के शीशे पर जमी बर्फ की जगह पानी था।

जिस डाइनिंग टेबिल पर मेहमान भोजन करते थे, वहां इस पर गहन चर्चा चल रही थी कि अगर बर्फ ही न हो, तो स्की रिजॉर्ट का क्या मतलब रह जाएगा! 'हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई चीज खत्म हो रही है। तभी हम कोई दूसरा काम शुरू कर पाएंगे', गेस्ट हाउस का मैनेजर कह रहा था।

एरिका सोलोमन

ज्युरिख से 30 मील दूर के शहर सैंटेल के लोगों तथा रिजॉर्ट्स के कर्मचारियों के लिए यह मानना कठिन है कि स्कीइंग के दिन अब गिने-चुने ही रह गए हैं।

जिस देश में हर आदमी स्कीइंग करता है, वहां बर्फ का घटते जाना सिर्फ आर्थिक नुकसान या पर्यावरणीय खतरा नहीं, बल्कि यह उसकी राष्ट्रीय पहचान को खतरा है।

ज्युरिख से 30 मील दूर बसे शहर सैंटेल के अनेक गांवों के लोगों तथा रिजॉर्ट्स के कर्मचारियों के लिए यह मानना कठिन है कि स्कीइंग के दिन अब गिने-चुने ही रह गए हैं। पृथ्वी के गर्म होने के कारण यूरोप में भी जलवायु संकट के लक्षण दिखने लगे हैं। विगत गर्मी में यूरोप के अनेक इलाकों में सूखा पड़ा और रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ। इस साल सर्दी में अनेक जगह तापमान सामान्य से इतना अधिक दर्ज हुआ कि कई स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ ही नहीं दिखी। स्विट्जरलैंड के लिए, जिसकी बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और ग्लेशियर यूरोप में जलापूर्ति के बड़े स्रोत हैं, बढ़ता तापमान खतरे की घंटी है। इस कारण पिछले साल स्थानीय ग्लेशियरों का घनत्व छह फीसदी घट गया। देश के कुछ इलाकों में स्कीइंग उद्योग के लिए भी, जिसकी सालाना कमाई 5.5 अरब डॉलर है, यह नई चुनौती है। पर जिस देश में लगभग हर आदमी स्कीइंग करता है, उसके लिए बर्फ का गायब होना सिर्फ आर्थिक नुकसान या पर्यावरणीय खतरा नहीं है, बल्कि यह उसकी राष्ट्रीय पहचान को खतरा है। समुद्र तल से 5,250 फीट की ऊंचाई पर बसे सैंटेल शहर के लोगों को लगता था कि उनके यहां बर्फ विलुप्त नहीं होगी। लेकिन जलवायु वैज्ञानिक अब कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण 6,500 फीट से नीचे बर्फ नहीं जमेगी। हालांकि 6,500 फीट पर भी पर्यटन स्थल कृत्रिम बर्फ का इंतजाम कर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकेंगे। 'स्कीइंग यहां के लोगों का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह जानना दुखद है कि बर्फ न होने के कारण यहां यह खेल धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा', बिसिज कहते हैं।

© The New York Times 2023

आंकड़े

जीडीपी में कृषि का योगदान

आजादी के बाद से देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार कम होता गया। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई है।

1955	45.86%
1975	40.31%
1995	28.27%
2018	17.10%
2021	19.90%

नोट : आंकड़े वित्त वर्ष के अनुसार हैं।
स्रोत : योजना आयोग; वित्त मंत्रालय

आज भी उस प्रहरी का कंकाल उपदेश देता है-'भागिए मत, अपने कर्त्तव्य-स्थल पर डटे रहिए; क्योंकि मनुष्य का गौरव इसी में सन्निहित है।'

भागिए मत, डटे रहिए

रोम के पोंपाई नगर के निकट एक बड़ा ज्वालामुखी फटा। वह विशाल नगर खंडहर बनकर सदा के लिए विलीन हो गया। यह बात केवल इतिहास के पन्नों पर धुंधली-सी अंकित रह गई थी। किसे मालूम था कि यह नगर अभी बिल्कुल ही नष्ट नहीं हुआ। भू-तत्ववेत्ताओं ने उन टीलों को खोदा, तो उनमें से प्राचीन गौरव की गवाही देता एक सुंदर नगर का भग्नावशेष निकल आया। उस समय भूकंप से बचे लोगों ने कुछ संस्मरण लिखे थे, जो अब तक सुरक्षित हैं। उनमें लिखा है-जब भूकंप आया, तो लोग भागने लगे। जिसे जहां बन पड़ा, भागा। भागने वालों में से कुछ ने राजद्वार के प्रहरी से कहा–'चलो, तुम भी भाग चलो।' उसने कहा–'मेरा कर्त्तव्य मुझे अपने फर्ज से हटने की आज्ञा नहीं देता।' वह खड़ा रहा और उस महान नगर के साथ समाधिस्थ हो गया। जब राजद्वार तक खुदाई पहुंची, तो पाया गया कि एक प्रहरी का कंकाल ज्यों-का-त्यों खड़ा है। प्रहरी चाहता तो दूसरे लोगों की तरह भाग सकता था, पर कर्त्तव्य ने उसे ऐसा करने से रोक दिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

रोम में उस कंकाल को शाही सम्मान दिया गया और पूरे देश ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भी उस प्रहरी का कंकाल उपदेश देता है–'भागिए मत, अपने कर्त्तव्य-स्थल पर डटे रहिए; क्योंकि मनुष्य का गौरव इसी में सन्निहित है।'

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 12 मई, 1987

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को वैध ठहराया

राजीव के खिलाफ चुनाव याचिका रद्द

नई दिल्ली, ११ मई (वा)। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से १९८१ में उपचुनाव के विरुद्ध चुनाव याचिका को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को आज वैध ठहराया।

उच्च न्यायालय ने याचिका इस आधार पर रद्द की थी कि उसमें यह नहीं बताया गया था कि वह किस आधार पर दाखिल की गई और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया तथा न्यायाधीश के.एन. सिंह की खंडपीठ ने

उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी के अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1981 में उपचुनाव के विरुद्ध याचिका को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को वैध ठहराया। याचिका में यह नहीं बताया गया था कि वह किस आधार पर दाखिल की गई थी।

पारिस्थितिकी के अनुरूप हो विकास

जिन गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो, उनकी आबादी को तलहटियों की राजस्व भूमि पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

आर. विक्रम सिंह, पूर्व सैनिक व प्रशासक

आपदा

करीब पांच करोड़ वर्ष पहले जब यूरेशियन टैक्टोनिक प्लेट से भारतीय प्लेट आकर टकराई, तो हिमालय का उभार प्रारंभ हुआ। विश्व से डायनासोरों का राज खत्म हो रहा था। उसके बाद करोड़ों वर्षों के जैविक विकास एवं भौगोलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव सभ्यता का उद्भव हुआ और पामीर के पठार, हिमालय व हिंदूकुश पर्वत श्रृंखलाएं बनती चली गईं। भारतीय प्लेट आज भी पांच सेमी प्रति वर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है, फलस्वरूप हिमालय लगातार ऊंचा होता जा रहा है। यह चलता रहेगा, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। अतः कह सकते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे अस्थिर पर्वत श्रृंखला है। इसी कारण हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र बन जाता है। भूगर्भीय दबाव व पर्यावरणीय परिवर्तन स्थिर नहीं होते, लगातार चलते रहते हैं।

सवाल है कि क्या मानव सभ्यतागत विकास,

शहरीकरण, विकास संबंधी कार्य-बांध, सड़क व सुरंग निर्माण पर्यावरण के इस हिमालयी संकट के कारण हैं? इसका कोई सीधा उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। आप नहीं जानते कि 1991 में उत्तरकाशी में आया 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप, जिसमें बड़े पैमाने पर धन-जन व पर्यावरण की क्षति हुई थी, उसमें कितना हिस्सा टैक्टोनिक प्लेट के तनाव की उर्जा का है और कितना अनियंत्रित नगरीकरण व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का। जोशीमठ यदि बिना आबादी का मात्र वनक्षेत्र ही होता, तो क्या यह धंसान, जो जियोलोजिकल कारणों से हो रहा है, न हुआ होता? यह कहना संभव नहीं है।

भूगर्भीय परिवर्तन की ऊर्जा बहुत व्यापक है। उस पर मानवीय नियंत्रण असंभव है। हमें पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को समायोजित करना चाहिए, उसका अतिक्रमण करके नहीं।

दरअसल जो महत्वपूर्ण है, वह है हमारा आपदा प्रबंधन, जो अत्यंत उच्चकोटि का विश्वस्तरीय होना चाहिए। खतरे का सही आकलन, चेतावनी का प्रेषण, आबादी की आपात निकास व्यवस्थाएं न की गईं, तो जन-धन की क्षति से बचा न जा सकेगा। मैं उत्तरकाशी भूकंप त्रासदी के समय गढ़वाल में नियुक्त था। मैंने देखा कि जो मकान पत्थर व लकड़ी की पुरानी पद्धतियों से बने थे, उनकी क्षति कंकरीट-सरिया से बने मकानों की तुलना में कम थी। पहाड़ों के गांव व मकान हजारों वर्ष के पर्यावरणीय अनुभवों के अनुसार विकसित हुए हैं। बिना पर्वतीय ढलान का सहारा लिए आयतित डिजाइनों पर खड़े कर दिए गए मकान पर्यावरण आपदाओं को झेल नहीं पाते। प्रायः संकट का कारण बनते हैं।

पर्वतों के वनीकरण का ह्रास पारिस्थितिकी संकट का एक बड़ा कारण है। देवभूमि में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने के नाम पर बड़े पैमाने पर होटलों, गेस्टहाउसों, नागरिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। हमने नदियों के किनारों की नजूल जमीनों पर पांच से आठ मंजिला नए मंदिरों का निर्माण देखा है। इन अवैध निर्माणों के नक्शे तो कोई भी प्राधिकरण पास ही नहीं कर सकता, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर रहे ये निर्माण पर्वतों के सीमित संसाधनों पर भार बने हुए भविष्य की त्रासदियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जहां आबादी का दबाव पर्यावरणीय सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा हो, वहां दीर्घकालिक योजनाएं अमल में लाई जा सकती हैं। वन एवं राजस्व विभाग एक संयुक्त रणनीति पर कार्य कर सकते हैं। जिन गांवों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में समस्या हो रही है, उनकी आबादी को तलहटियों की राजस्व भूमि पर लैंड एक्सचेंज नीति के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। जो गांव पहाड़ पर एक सौ एकड़ का था, उसे यदि मैदान में राजस्व या वन भूमि में ले आया जाए, तो संभवतः 50 एकड़ भूमि ही उनके लिए अतिसुविधाजनक होगी। इस तरह पर्वतीय आबादी के वे बहुत से गांव, जिनके भविष्य में पर्यावरणीय संकट में फंस जाने की आशंका है, सुरक्षित ले आए जा सकेंगे। वन विभाग के स्वाभाविक वनीकरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप वन क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य की भी पूर्ति हो सकेगी। हमारा संकट अस्थिर क्षेत्रों में हुए अनियंत्रित बसाहट को लेकर है। कोई कारण नहीं कि पर्यावरण व प्रकृति, पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करते हुए हम कोई मध्यमार्ग न निकाल सकें।